भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 683

(जिसका उत्तर मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022/22 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है)

रुपये के अवमूल्यन के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी

683. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रुपए के निरंतर अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार द्वारा गत एक वर्ष में उठाए गए सार्थक कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अमेरिकी डॉलर की बढ़ती कीमतों के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गत दो वर्षों में कितना कम हुआ है; और

(ग) भारतीय रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की बढ़ती कीमत के कारण भारत में किन-किन वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि हुई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (चौधरी पंकज श्री)

(क): भारतीय रूपए का मूल्य बाजार-निर्धारित है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ जैसे ही भू-राजनीतिक तनावों से वैश्विक वचनबद्धताएं और दुनिया भर में आक्रामक मौद्रिक नीति सख्त हुई, अमरीकी डॉलर इस वित्तीय वर्ष में (30 नवंबर, 2022 तक) 7.8% मजबूत हुआ जहां चालू वित्त वर्ष में 30 नवम्बर, 2022 तक भारतीय मुद्रा में 6.9% की गिरावट आई, इसने वित्तीय वर्ष के दौरान चीनी रेनमिनबी (10.6%), इंडोनेशियाई रुपिया (8.7%), फिलीपीन पेसो (8.5%), दक्षिण कोरियाई वोन (8.1%), ताइवानी डॉलर (7.3%) आदि सहित अधिकांश एशियाई समकक्ष मुद्राओं से बेहतर प्रदर्शन किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) विदेशी मुद्रा बाज़ारों की बारीकी से निगरानी करता है और किसी भी पूर्व-निर्धारित लक्ष्य स्तर या बैंड के संदर्भ के बिना, विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करके केवल व्यवस्थित बाज़ार स्थितियों को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करता है।

आरबीआई ने हाल की अवधि में विनिमय दर की अस्थिरता को कम करने और वैश्विक वचनबद्धताओं को कम करने के लिए, विदेशी मुद्रा निधियन के स्रोतों में विविधता लाने और विस्तार करने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

- वृद्धिशील विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] और अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमा देनदारियों को 4 नवंबर, 2022 तक जुटाई गई जमा राशि के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) रखने से छूट दी गई थी।
- ताजा एफसीएनआर (बी) और एनआरई जमाओं को 31 अक्टूबर, 2022 तक ब्याज दरों पर मौजूदा विनियमन से छूट दी गई थी (यानी ब्याज दरें बैंकों द्वारा तुलनीय घरेलू रुपया सावधि जमा पर दी जाने वाली दरों से अधिक नहीं होंगी)।
- इसके अलावा, भारतीय ऋण लिखतों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण प्रवाह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से संबंधित नियामक व्यवस्था में संशोधन किया गया है।
- विदेशी वाणिज्यिक उधारी सीमा (स्वचालित मार्ग के तहत) को बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है और 31 दिसंबर, 2022 तक चुनिंदा मामलों में समग्र लागत सीमा को 100 आधार अंकों तक बढ़ा दिया गया है।
- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी 1 बैंक विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर लागू अंतिम उपयोग आदेशों के लिए विदेशी मुद्रा में उधार देने के लिए ओवरसीज विदेशी मुद्रा उधार का उपयोग कर सकते हैं।
- भारत से निर्यात की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जुलाई, 2022 में भारतीय रुपये में बीजक, भुगतान और निर्यात/आयात के निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था की है।

(ख) : देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो 27 नवंबर, 2020 को 574.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, 25 नवंबर, 2022 तक घटकर 550.14 बिलियन अमरिकी डॉलर हो गया। इस गिरावट के लिए प्रधान रूप से पुनर्मूल्यांकन परिवर्तनों को उत्तरदाई माना जा सकता है जो अमरीकी डॉलर की तुलना में अन्य विदेशी मुद्राओं जैसे कि यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड आदि के विनियोजन साथ ही साथ विदेशी प्रतिभूतियों के बढ़ते प्रतिफलों के कारण उपजी।

(ग) : अन्य कारकों के अपरिवर्तित रहते विनिमय दर मूल्यह्रास से आयातित वस्तुओं के महंगे होने के परिणामस्वरूप आयातित वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ने की संभावना है। घरेलू कीमतों पर समग्र प्रभाव आयात कीमतों की घरेलू कीमतों के पारगमन पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, विनिमय दर मूल्यह्रास से देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि, नगण्य विनिमय दर केवल एक कारक है जो निर्यात प्रतिस्पर्धा और आयात की लागत को निर्धारित करता है और इसलिए समग्र व्यापार संतुलन बना रहता है। इसलिए, व्यापार संतुलन और साथ ही चालू खाता शेष के अन्य घटकों पर विनिमय दर की उतार-चढ़ावों के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता है।

******